Sharad Pawar Committee report on power Sector

1393. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has ordered a fullflcdged review of the power sector;

(b) whether the three year old Sharad Pawar Committee report which had called for far-reaching changes in the electricity sector, is being reconsidered by the Planning Commission;

(c) whether the Planning Commission has accepted the recommendations contained in the said Report; and

(d) if so, the steps being taken by the Planning Commission to direct the Ministry of Power to implement those recommendations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Ninth Plan exercise will include a detailed review of the power sector.

(b) to (d) The recommendations of the Sharad Pawar Committee Report on Power Sector are presently under examination in the Planning Commission. The Report will be placed before the National Development Council after the implications are fully examined.

Employment Policy and programme in the Country

1394. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROG RAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any employment policy and programme for the educated and uneducated youngmen in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) what steps have been taken by Government to create job opportunities in the organised sectors of economy during the last three years, till date?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (d) Expansion of employment oppor tunities through growth of sectors and sub-sectors with high employment intensi ty such as agriculture, agro and rural industries, rural infrastructure, small and the decentralised manufacturing sector, urban informal sector and services re mains a thrust area in the Five Year Plans. The Ninth Plan will implement a National Employment Assurance Scheme.

Special employment programmes are in operation to provide supplementary employment in both rural and urban areas for both educated and uneducated persons. Recognising the high incidence of under employment and increasing casual-isation of labour, there is need to enhance employment opportunities for the poor.

The organised sector employment during the last three years in the public and private sectors are as under:

(lakh persons)

	Public Sector	Private Sector	Total organised
1993	193.26	78.51	271.77
1994	194.45	79.30	273.75
1995	194.66	80.59	275.25

मध्य प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिये धनराशि दिया जाना

1395. **श्री अजीत जोगी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्यन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई,

(ख) क्या सरकार का राज्य में इन योजनओं के कार्यान्वयन हेतु अधिक धनराशि स्वीकृत करने की विचार है, और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलध) : (क) गरीबी कम करने के कार्यक्रमों अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए.एम) और शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाएं (यू.बी.एस.पी.) और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम.आई.) यू.पी.ई.पी.) के कार्यान्वयन के लिए आठवीं योजना (1994-95 से 1996-97 तक) के अंतिम तीन वर्षो में मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय निधियों का आबंटन संलग्र विवरण में दिखाया गया है । (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) इसके अलावा 1996-97 में मध्य प्रदेश राज्य को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अतंर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 144.99 करोड़ रूपये की धनराशि और झोपंड-पट्टी विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 14.80 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है । चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए गरीबी कम करने के कार्यक्रमों हेतु आवंटन पहले ही किया जा चुका है । अतः मध्य प्रदेश राज्य के लिए आठवीं योजना की शेष अवधि में इन कार्यक्रमों के लिए किसी अतिरिक्त आवंटनो का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य के लिए आठवीं योजना (1994-95 से 1996-97) के अंतिम तीन वर्षो के दौरान गरीबी कम करने संबंधी कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय निधियों का आबटंन

(लाख रुपए में)

स्कीम	1994-95	1995-96	1996-97
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5287.00	5282.69	5282.69
जवाहर रोजगार योजना	27471.67	34819.57	17611.61
तीव्रीकृत जवाहर रोजगार योजना	121195.00	6076.00	---
नेहरू रोजगार योजना	508.30	480.00	480.00
गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं	117.45	116.15	116.15
प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	---	772.87	682.67

* केन्द्रीय रूप से जारी क्योंकि कोई आवंटन नहीं किए जाते ।

** नवम्बर, 1996 तक जारी